

अब बापूधाम एक्सप्रेस रुकेगी सिसवां बाजार स्टेशन: केन्द्रीय मंत्री ने हरीझंडी दिखाकर किया ट्रेन को रवाना

(आधुनिक मसाचार सेवा)

वाराणसी। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री जनता की सुविधा हेतु गाड़ी सं 012537/12537 एक्सप्रेस रेलवे प्रशासन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, इसके पूर्व यह गाड़ी सं 12538 के लिए भी स्टेशन पर प्रायोगिक आधार पर हराव 5 सितम्बर 2022 से अगली सूचना

सम्पादकीय

पक्षियों की रोचक दुनियास्त
विलुप्त होने की कगार पर कई
गिर्वाल प्रजातियां ए पर्यावरण के
लिए यह गंभीर संकट का विषय

1990 के दशक के मध्य से 2007 के दौरान इन 99ग्रॅंड सफेद दुम वाले गिर्दु गायब हो गए और अब भारत में उनकी संख्या केवल 64000 रह गई है। इस गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिर्दु को अब छिट्ठिकली ऐनदेनजर्दी प्राणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसी तरह की बदकिस्मती का सामना लम्बे बिल वाले गिर्दु को भी करना पड़ा एंजिसकी आबादी में लगभग 97% की भारी गिरावट देखी गई। एक कडक सर्द दुपहरी को एक राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमा के बीच चलने वाली चम्बल नदी के नालों पर ए सूर्य के स्वर्ण किरणों से मानो आग सौ लगी थी। रेत के किनारे और छड़ान की सतहों पर मगरए घड़ियाल धूप का आनंद ले रहे थे और नद. कछुए चंबल की सुरक्षा में आलसपूर्ण तैराकी कर रहे थे। तभी सफारी नाव के पहुँचने से उनकी निर्धारित सुरक्षित सीमा कि दूरी भांग सी हो गई। इन्हीं नालों के किनारे एक रेशमी सूती के ऊँचे पत्ते झड़े हुए पेड़ पर ए मिस्त्र देशीय गिर्दु का एक समूह बैठा था। उनमें से एक नर और एक किशोर गिर्दु एकाएक उड़ निकले और चम्बल और उसके नालों पर एक के बाद एक बढ़ते हुए संकिंचिक चक्कों में उड़ान भरने लगे। कदाचित अन्यतंत सर्द रात्रि से पहले यह उनके लिए भोजन कर निश्चिंत होने का समय था। लगता था जैसे आकाश से उनकी तीक्ष्ण निगाहें भोजन के लिए नीचे फ़ैहड़ बेरंग नालों को तलाश रही हों। तथ रूप से गिर्दु का आहार मृत जानवरों का मांस होता है और ऐसे समय में यह सरलता से माना जा सकता है कि मृत मवेशी इन गिर्दु के लिए एक सहज भोजन का उपाय होंगे। किन्तु सन 1990 से ही इस इलाके में गिर्दु होना आसान नहीं रहा है। एक अबोध गिर्दु के रामायण के प्रसिद्ध पात्र जटायु के समय से ही गिर्दु ने भारतीय लोकनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान पाया है। यद्यपि देश स्तरीय दीर्घकालिक जनसंख्या अनुमान शायद ही उपलब्ध होने भारत में 1990 के दशक की शुरुआत तक लाखों गिर्दु थे। भारतीय उपमहाद्वीप में गिर्दु की नौ प्रजातियां पाई जाती हैं। सफेद दुम वाले जिप्स बैंगलोंसिस ए लंबे चौंच वाले जीण इंडिकस ए पतले चौंच वाले जीण टेनुइरोस्ट्रिस ए लाल सिर वाले सरकोजिप्स कैल्वस ए मिस्त्र देशीय गिर्दु नियोफ़ॉन पर्कनोप्टरेस ए

जीडीपी की विकास दर की निरंतर बढ़नी रहे, तब आराम से आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत

आत्मनिर्भर भारत, मुद्रा क्रण, मेक इन इंडिया फॉर्वर्ड वर्ल्ड जैसी क्षेत्रवार लक्षित उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं और रक्षा एवं उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आयात प्रतिस्थापन जैसी पहलों ने भविष्य के लिए एक मजबूत विकास मंच तैयार किया है। विन्त तर्फ 2022-23 की अपैल-

थी। इसलिए 13.5 फीसदी का आंकड़ा भले मजबूत दिख रहा हो, लेकिन रिजर्व बैंक एवं बाजार की उम्मीदों से कम है। पिछले साल इसी अवधि में भारत की जीडीपी में 20.1 फीसदी की वृद्धि हुई थी। यह काफी हृद तक काविड-19 और लॉकडाउन के कारण कम आधार रखे जाने के कारण था। इसके



जून की तिमाही में देश की सकल घरेलू विकास (जीडीपी) दर 13.5 फीसदी हो गई, जो पिछली चार तिमाहियों में सबसे तेज है। विकास दर में यह तेज वृद्धि कृषि एवं विनिर्माण में सुधार तथा सेवा क्षेत्र के लाभग्र पूरी तरह से खेल जाने के कारण हुई है। हालांकि, यह वृद्धि अब भी रिजर्व बैंक के हालिया पूर्णानुमान (16.2 फीसदी) से कम है। 51 अर्थसांस्कृतियों वाले रॉयटर्स सर्वेक्षण में भी अपने यहां पहली तिमाही में 15.2 फीसदी सालाना विकास दर की भविष्यवाणी की गई चलते अप्रैल-जून 2020 में जीडीपी में -23.8 फीसदी की बहुत तेज गिरावट देखी गई। इस संख्या को संदर्भ में रखने के लिए, आइए, कोविड पूर्व जीडीपी की तुलना जीडीपी पर कोविड के तीन वर्षों के प्रभाव से करते हैं। अप्रैल से जून, 2018 के दौरान जीडीपी 33.82 लाख करोड़ रुपये थी। यह अप्रैल से जून, 2019 में बढ़कर 35.49 लाख करोड़ रुपये हो गई। जैसे ही कोविड लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, अप्रैल से जून, 2020 के दौरान जीडीपी तेजी से गिरकर 27.04 लाख करोड़ रुपये रह गई।

विश्वविद्यालयों में शिक्षक के पदों पर स्थायी नियुक्ति करने से सुधरेगी शिक्षा की गुणवत्ता

देली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में स्थायी शिक्षकों से अधिक तर्दय शिक्षक काम कर रहे हैं। कुछ महाविद्यालयों में तो स्थिति यह है कि 70 से 80 प्रतिशत तर्दय शिक्षक काम कर रहे हैं। जबकि यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार 10 प्रतिशत से ज्यादा तर्दय शिक्षक नहीं होने चाहिए। विवि से नियुक्ति से जुड़ा रोस्टर विवाद पहली बार वर्ष 2006 में सामने आया था। उस बत केंद्रीय विवि में ओबीसी आरक्षण के तहत नियुक्तियों के संगल के समाधान के लिए तत्कालीन सरकार के कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण मंत्रालय ने यूजीसी से विवि में आरक्षण लागू करने की खामियों को दर करने का निर्देश दिया था।

नियुक्ति से जुड़ा रोस्टर विवाद फली बार वर्ष 2006 में सामने आया था। उस वक्त केंद्रीय विवि में ऑबीसी आरक्षण के तहत नियुक्तियों के सवाल के समाधान के लिए तत्कालीन सरकार के कार्मिक तथा प्रशिक्षण मंत्रालय ने यूजीसी से विवि में आरक्षण लागू करने की खामियों को दृग् करने का निर्देश दिया था। किसी विवि के सभी विभाग में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर एवं असेसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का तीन स्तर पर कैडर बनाने की अनुशंसा की गई। कमेटी ने विभाग की बजाय विविए कालेज को यूनिट मानकर आरक्षण लागू करने की संस्तीत कीए क्योंकि उक्त पदों पर नियुक्तियां विवि करता है न कि

केंद्रीय विवि में अक्टूबरए 2021 तक कुल स्वीकृत 18ए905 संकाय फैकल्टीद्ध पदों में से 6ए333 शिक्षकों के पदिरक्त थे। उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की कमी का आलम ये है कि जेन्यू और ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान में शिक्षक संकाय के 326 पद रिक्त हैं। सेवानिवृत्तिए त्यागपत्र और छात्रों

विवि में न सिर्फ़ शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है एवं बल्कि इससे शिक्षकों की कमी चिंताजनक बनी हुई है। जो शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय विवि में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने में मुश्तोद न होए वह राज्यों से कैसे यह कह सकता है कि वे इस मामले में तेजी दिखाएं यह बेवजह नहीं है कि प्रयोगशालाओं और पूर्स्तकालयों एवं खेल परिसरों आदि में सुविधाओं और संसाधनों के घोर अभाव से जूझते विवि की सबसे बड़ी समस्या आज शिक्षकों की कमी हो चुकी है जिसके चलते शैक्षणिक सत्र समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इन संस्थानों से निकलने वाले विद्यार्थियों के बीच विदेश में प्रतिभा पलायन और शिक्षण को करियर के रूप में न चुनना शिक्षकों की कमी की एक वजह हो सकती है। एक प्रश्न-यह भी है कि खाली पदों को भरने की प्रक्रिया इन्हीं धीमी क्र्यों हैं इसी तरह क्या वजह है कि विवि के कुलपति करिक्त पद भी मुश्किल से भरे जा पा रहे हैं और शिक्षकों के रिक्त पद भरने के मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि देश में योग्य शिक्षक नहीं रह गए हैं। कई बार यह सुनने को मिलता है कि उच्च शैक्षणिक संस्थान शिक्षा के आवश्यक मानकों पर खरे नहीं उत्तर रहे हैं। परंतु जब इन्हीं बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हों तो दूसरे मानकों पर वे कैसे खरे उत्तर सकते हैं? उवर्ष 2015-16 की तुलना में 2019-20 में विवि की संख्या में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के अनुरूप शैक्षणिक और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत नहीं किया गया है। देश के विवि में शिक्षकों के रिक्त पद भरने का काम भले ही धीमी गति से हो रहा होए लेकिन उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लेने वाले युवाओं की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। इस मसले पर जारी वर्षिक रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात पहली बार 25 प्रतिशत से अधिक हुआ है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सरकार तत्परता दिखाकर आने वाले समय में जल्दी ही योग्य एड्हाक शिक्षकों को स्थायी नियुक्ति देंगी। यहां एक सुझाव यह भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों की स्थायी नियुक्तियों से पूर्व रोस्टरए काले कमेटी की रिपोर्ट 10 प्रतिशत अतिरिक्त ईडब्ल्यूयूएस आरक्षण लगाय करते हुए व विज्ञापनों की सही से जांच कराने के लिए एक पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी बनाई जानी चाहिए और जो भी बैकलाग पद हैं उसे भरने के लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। अभी प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की उम्र और कुलपतियों के कार्यकाल की सीमा भी अलग अलग राज्यों में अलगअलग है। ऐसे में भी राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति की जरूरत है। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबी है और इसमें प्रक्रियागत औपचारिकताएं बहुत अधिक हैं। ऐसे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्टैंडिंग कमिटी के इस सुझाव को अमल में लाया जाना चाहिए जिसमें कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया पद के रिक्त होने से पहले ही शुरू कर दी जानी चाहिए।

A photograph of a woman from behind, wearing a pink sari with a gold border and a blue face mask. She is looking towards a screen or a presentation board. In the background, another person is visible, also wearing a face mask. The setting appears to be an indoor classroom or workshop environment.

A photograph showing a group of students in a classroom. They are all wearing face masks and appear to be focused on their work at their desks. The students are dressed in various attire, including a red plaid shirt and a blue mask. The classroom has wooden desks and chairs.

जिहादी आतंकवाद और लव जिहाद को लेकर सुर्खियों में झारखंड

झारखंड के दुमका में अंकिता नामक युवती की हत्या पर लोगों का आक्रोश थमा भी नहीं था कि वहाँ से एक आदिवासी लड़की की दुर्कर्म के बाद हत्या की खबर आ गई। सामान्य स्थिति में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि एक लड़की अपने घर में सोई हो और उसे भौंर में पेटोल फैंक कर जला दिया जाए। अंकिता को जलाए जाने के कुछ घंटे बाद ही यह खबर गयरल हो गई। यदि झारखंड सरकार कोई पछतावा है। जधन्य अपराध करने वाला कोई शख्स गिरफ्तारी के बाद ऐसे मुस्कुराए मानो उसने कुछ गलत किया ही नहीं और उसे कुछ होगा नहीं या जो होगा, उसकी उसे कोई परवाह नहीं तो फिर इसके कारणों की अलग तरीके से छनबीन करने की आवश्यकता महसूस होती है। हमारे देश में कई बार सच बोलना अपराध बन जाता है। दुनिया भर के जिहादी भय और घबराहट में आतंकी घटना को

बातें होंगी जो सामने नहीं आई होंगी। पलामू जिले के मुरुमातृ गांव में मुसलमानों के एक समूह ने 20 दलित परिवारों के घरों को यह कहकर धस्त कर दिया कि वे मदरसे की जमीन पर बने थे। पिछले मार्च में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते ने देवबंद से इनामुल हक उर्फ इनाम इनियाज का गिरफ्तार किया। लश्कर-ए-तैयबा से उसके संबंध के प्रमाण मिले और पता चला कि वह आतंकी

दिया गया था। इंडियन मुजाहिदों का एक बड़ा तंत्र झारखंड में पाया गया था। पिछली जुलाई में प्रथमनमंत्री की पटना यात्रा के एक दिन पहले 11 जुलाई को पटना से मुलवारी शरीफ तक पीएफआई का जो बहुर्वित माड्यूल पकड़ में आया, उसका प्रमुख जलालुद्दीन झारखंड के कई थानों में दरोगा के रूप में कार्य कर चुका है। पिछले 10 जून को जुमे की नमाज के बाद रायों में जिस ढंग का उत्पात

भारत-बांग्लादेश संबंधों को नया आयाम देने का अवसर, मगर कुछ अवरोध अभी भी कायम

ब्रिगेडियर आरपी सिंह : बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का चार दिवसीय भारत दौरा आरंभ हो गया है। भारत-बांग्लादेश के संबंध बहुत विशिष्ट हैं, क्योंकि बांग्लादेश के स्वतंत्र अस्तित्व में भारत की निर्णायक भूमिका रही। स्वयं मुझे बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में सेवा देने का अवसर मिला। उस वक्त की तमाम यादें मेरे जेहन में आज भी जिंदा हैं। मुझे भलीभांति याद है कि कैसे दोनों पक्षों के सैनिकों ने ए राष्ट्र के सृजन में अपना रक्त बहाया था। कई बार तो यही पहचान में नहीं आता था कि बलिदानी सैनिक भारतीय हैं या बांग्लादेशी। हम लोग न केवल उस आतंकीयों के विरुद्ध लड़े जिसमें सभी मानवीय मूल्यों को तिलांजलि दे दी थी, बल्कि हमारा संघर्ष भावी पीढ़ी की समृद्धि को सुनिश्चित करने से भी जड़ा था। 51 साल पहले दोनों देशों के बीच सीमा की वह रेखा धूंधली पड़ गई थी, जब बांग्लादेश (तब पूर्वी पाकिस्तान) में सताए जा रहे लाखों लोगों के लिए भारत ने अपने दरवाजे खोल दिए थे। भारत उस समय गरीब देश ही था, लेकिन इसके बावजूद उसने इंसानियत और बड़ा दिल दिखाया। भारतीय सेना के मन में कभी ऐसा भाव नहीं आया कि बांग्लादेशी सेना या मुक्ति वाहिनी किसी और देश से जुड़ी है और हमें कभी अहसास नहीं हुआ कि हम किसी दूसरे देश के लिए लड़ रहे हैं। मात्र 12 दिनों



इसकी गंभीरता को समझती तो उसे बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया जा सकता था। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री चाहे जितने आक्रमक बयान दें, इस जघन्य अपराध के तीन दिनों तक लगा ही नहीं कि झारखंड में कोई संवेदनशील सरकार भी है। इस घटना पर मुख्यमंत्री हमें तक सोरेन का वक्तव्य पार्चें दिन आया। हमें तक सोरेन सरकार की कानून-व्यवस्था संबंधी नीतियां कार्फी समय से आलोचना के घेरे में हैं। प्रश्न है कि अंकिता को जलाकर मारने वाले शाहरुख ने ऐसा क्यों किया होगा? झारखंड प्रशासन को सोचना चाहिए कि कोई वैसा दूस्साहस करें कर सकता है, जैसा शाहरुख ने किया पिछले कुछ वर्षों में झारखंड की घटनाओं को देखें तो इसके एक दूसरे खतरनाक पहलू की ओर भी दृष्टि जाती है। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद जिस ढंग से शाहरुख मुस्कुरा रहा था, उससे ऐसा लगा है नहीं कि उसे अपने किए पर अंजाम नहीं देते। ज्यादातर मानसिक रूप से स्थिर अवस्था में स्वयं को आत्मघाती विस्फोटक बनाते हैं। ऐसे आतंकियों पर की गई छनबीन बताती है कि उन्हें विशेष आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि वे मानते हैं कि मजहबी आदेश का पालन कर रहे हैं। शाहरुख के बारे में अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, जिससे यह मान लिया जाए कि वह अतिगादी मजहबी कट्टरता से भरा हुआ था, किंतु इस आशंका को खारिज भी नहीं किया जा सकता। झारखंड देश में मुस्लिम कट्टरवाद और जिहादी आतंकवाद के साथ लव जिहाद की दृष्टि से हमेशा सुखियों में रहा है। झारखंड के जामताड़ा में अनेक स्कूलों में प्रार्थना के तरीके बदले जाने का मामला सामने आया। वहां मुसलमानों के एक समूह ने कहा कि वे बहुत मैं हैं तो उनके अनुसार ही प्रार्थना होनी चाहिए। इसी तरह रविवार की जगह शुक्रवार को स्कूल में छुट्टियां हो रही थीं। ये घटनाएं सामने आ गईं लेकिन ऐसी भी काँड़

गतिविधियों में शामिल होने की तैयारी कर रहा था। यह झारखण्ड का पहला एसा मामला नहीं। 2003 में दिल्ली के अंसलू प्राग्या विस्फोट मामले में शाहनवाज का नाम सामने आया था, जो जमशेदपुर का रहने वाला था। सितंबर, 2019 में झारखण्ड एटीएस ने अलकायदा से जुड़े कलीमउद्दीन मुजाहिरी को गिरफतार किया था। एटीएस ने बयान दिया कि इसकी गिरफतारी के साथ झारखण्ड में सक्रिय अलकायदा का स्तीरपर सेल ध्वस्त हो गया है। कलीमउद्दीन अलकायदा के सक्रिय आतंकी अब्दुल रहमान अली उर्फ कटकी, जो तिहाड़ जेल में बंद है, का सहयोगी था। कटकी के अलावा अब्दुल सामी, अहमद मसूद, राजू उर्फ नरसीम अखर और जीशान हैदर भी गिरफतार हुए। पीछे लौटे तो अक्टूबर, 2013 में पटना के गांधी मैदान में आयोजित नरेन्द्र मोदी की सभा और जुलाई, 2013 में बोधगया में हुए आतंकी धमाकों के दोषी झारखण्ड से ही पकड़े गए थे। इसे रांची माड़ाल का नाम

हुआ, वह देश के सामने है। पुलिस ने हिंसा करने वालों में से कुछ की तस्वीरें चौराहे पर लगाई, पर उन्हें यह कहकर हटा दिया गया कि उनमें कुछ ग़इबड़ियां हैं और सही करके दोबारा लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पिछले सात-आठ वर्षों में ज़ारखंड ने लव जिहाद के मामलों में कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। 2014 में तारा शाहदेव नामक शूटर की बटना ने पूरे देश को चौकाया था। अंजीत कोहली नाम के एक शख्स ने उसे प्रेम जाल में फ़साकर शादी की, जो बाद में रकीबुल हसन निकला। उसके बाद से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अंकिता का मामला भी ऐसा ही जान पड़ता है। अंकिता मामले की जांच मुस्लिम कट्टरवाद के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है, लेकिन जो सरकार पुलिस पर हमला करने वाले हसक तत्वों की तस्वीरें लगाकर हटा सकती है, वह सच सामने लाने वें लिए प्रतिबद्धता दिखाएगी। इसमें संदेह है।

